



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 29 सितम्बर, 2009 / 7 आश्विन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 सितम्बर, 2009

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-27 / 2009-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-09-2009 को अनुमोदित इन्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2009

(भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उच्चतर शिक्षा के लिए इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम इण्डस. इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2009 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं.—इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रबन्ध बोर्ड” से इस अध्यादेश की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) “परिसर” (कैम्पस) से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) “दूरवर्ती शिक्षा” से संचार, अर्थात् प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, से सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत शिक्षक और विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारिवृन्द है;

(ङ) “फीस” से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है ;

(च) “सरकार” या “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) “शासी निकाय” से इस अध्यादेश की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) “उच्चतर शिक्षा” से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) “छात्रावास” से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ञ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

- (ट) "परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित, कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो ;
- (ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ड) "विहित" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;
- (ण) "धारा" से इस अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है;
- (त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारथा ऐजुकेशन सोसाइटी, बम्बई, अभिप्रेत है;
- (थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधि के लिए, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;
- (प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और
- (फ) "विश्वविद्यालय" से इण्डस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, ऊना हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;
- (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;

- (घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;
- (ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;
- (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;
- (छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाँ संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है; और
- (ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन परिसर (कैम्पस) बाह्य केन्द्र स्थापित करना ।

4. निगमन.—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर इण्डस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, ऊना हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय बाथु, उप तहसील—हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य.—(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित, विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा प्रसार शिक्षा के लिए उपबन्ध करना;
- (ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना;
- (iii) निवेश—बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;
- (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यक्षीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियाँ तथा अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियाँ प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना;
- (v) मानद उपाधियाँ या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियाँ प्रदान करना;
- (vi) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;

- (vii) अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (viii) हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;
- (ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;
- (x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;
- (xi) विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;
- (xii) किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;
- (xiii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ़ ऐक्सीलेंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;
- (xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहकार करना;
- (xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;
- (xvii) विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अध्यादेश के विरुद्ध न हो, कोई करार करना;
- (xviii) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;
- (xix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

- (xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;
- (xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;
- (xxiv) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;
- (xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्यूल उपाधियां, डिप्लोमे या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;
- (xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों, अनुशासनों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;
- (xxvii) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और विद्या केन्द्र स्थापित करना; और
- (xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो के साथ जाति, वर्ग, रंग पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. **विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.**—विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. **सम्बद्धता की शक्ति का न होना.**—विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. **विन्यास निधि.**—(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए तीन करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपट्ट करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा ।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी।

9. साधारण निधि.—विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;
- (ग) परामर्शी—सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;
- (घ) वसीयतें, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।

10. साधारण निधि का उपयोग.—साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किसी भविष्य निधि अभिदाय, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;
- (ग) करों या स्थानीय उदग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;
- (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;
- (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) इस अध्यादेश की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा—परीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;
- (झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;
- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाए, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ड) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) रजिस्ट्रार;
- (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और
- (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.—(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का मुखिया (हैड) होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;
- (ख) कुलपति को नियुक्त करना;
- (ग) इस अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.—(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और, शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा; तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अध्यादेश के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय, में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार/संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.—(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

16. अन्य अधिकारी.—(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों ।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

- (i) शासी निकाय;
- (ii) प्रबन्ध बोर्ड;
- (iii) विद्या परिषद्; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

18. शासी निकाय.—(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :—

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;
- (घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;
- (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और
- (च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य ।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा—उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;
- (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;
- (ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (क) कुलपति;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं; और
- (घ) अध्यापकों में से, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यक्ति;

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्.—(1) विद्या परिषद् में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

21. अन्य प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.—कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

- (क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या
- (ख) अनुमोचित दिवालिया है; या
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या
- (ङ.) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नाम निर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता है।

25. समितियां.—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश के निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26. प्रथम परिनियम.—(1) इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किए जाएं;
- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (घ) कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, निबन्धन और शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
- (ङ.) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;
- (च) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थता के लिए प्रक्रिया;
- (छ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ज) छात्रों को शिक्षा फीस (ट्यूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियाँ तथा अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के संबन्ध में उपबन्ध;
- (झ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबन्ध;
- (ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबन्ध; और
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबन्ध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्तर्ती परिनियम.—(1) इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्तर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;
- (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;
- (घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;
- (ङ.) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में सीटों(स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और
- (झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अध्यादेश के उपबंधों अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासनों और अनुदेशों के मानदण्डों, शिक्षा और परीक्षा को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.—(1) इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमों, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;

- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ड.) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबन्ध ;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ञ) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है; और
- (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय, को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29. पश्चात्तर्ती अध्यादेश.—(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेशों को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधधीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अध्यादेश और तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.—(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ पाठ्येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

32. फीस संरचना.—(1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार तथा पुनरीक्षित करेगा और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और सरकार प्रस्ताव प्राप्ति के एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) करेगी :

परन्तु यदि सरकार एक मास के भीतर अनुमोदन सूचित (प्रदान) नहीं करती है, तो इसे सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को जारी करने से पूर्व विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीस:—

(क) निम्नलिखित के लिए:—

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रात जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी।

33. परीक्षाएं.—प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैडर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात् (अपश्चात्), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु यह कि किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य-शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे।

स्पष्टीकरण.—“परीक्षाओं की अनुसूची” से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्योरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्योरा भी सम्मिलित होगा ।

34. परिणामों की घोषणा.—(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, सरकार को प्रस्तुत करेगा । सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का पालन नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.—विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.—विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी), बंगलौर से अपनी स्थापना के तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय तत्पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.—इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.—(1) विश्वविद्यालय के तुलन पत्र सहित, वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उदभूत सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां।—(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार, कुलपति से परामर्श के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगी ।

(2) सरकार, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिश का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।—(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पंद्रह वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां।—(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अध्यादेश के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवर्तनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अध्यादेश के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवर्तनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे ।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और
- (घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

(5) इस अध्यादेश के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अध्यादेश के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवर्तनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सभी शक्तियां होंगी और वह इस अध्यादेश के अधीन शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड के सभी कर्तव्यों के अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं ।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा ।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त वित्त्तंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

43. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और
- (ख) अन्य विषय जो इस अध्यादेश के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे ।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक

सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमन्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

प्रभा राव,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 2009

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
ORDINANCE, 2009**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India. An Ordinance to provide for establishment, incorporation and regulation of Indus International University, for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause(1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2009.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.— In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Board of Management” means the Board of Management constituted under section 19 of this Ordinance;
- (b) “campus” means the area of University within which it is established;
- (c) “distance education” means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;
- (d) “employee” means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (e) “fee” means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;
- (f) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) “Governing Body” means the Governing Body constituted under section 18 of this Ordinance;
- (h) “higher education” means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
- (i) “hostel” means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centres, established or recognized to be as such by the University;
- (j) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
- (k) “off campus centre” means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University’s complement of facilities, faculty and staff;
- (l) “Official Gazette” means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (m) “prescribed” means prescribed by rules made under this Ordinance;
- (n) “regulating body” means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education, National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of

Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government;

- (o) “section” means a section of this Ordinance ;
- (p) “sponsoring body” means the Kartha Education Society, Mumbai, registered under the Societies Registration Act, 1860;
- (q) “State” means State of Himachal Pradesh;
- (r) “statutes”, “ordinances” and “regulations” mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Ordinance;
- (s) “student” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;
- (t) “study centre” means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;
- (u) “teacher” means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University; and
- (v) “University” means Indus International University, Una, Himachal Pradesh.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,—

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;
- (b) to establish facilities for education and training;
- (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;
- (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;
- (e) to establish campus in the State;
- (f) to establish examination centres;
- (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method; while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by regulating bodies; and
- (h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic

Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of Indus International University, Una, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall situate and have its head quarter at Bathu, Sub-Tehsil Haroli, Distt. Una, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely:—

- (i) to provide for instructions including the method of distant education in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;
- (ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;
- (iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;
- (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates to and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (v) to confer honorary degrees or other academic distinctions;
- (vi) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;
- (vii) to institute and award Fellowships, Studentships and Prizes;
- (viii) to establish and maintain Hostel including Halls; recognise guide, supervise and control Hostels including Halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;
- (ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and of the Colleges;
- (xi) to determine the criterion for admission into the University or its Colleges;
- (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;

- (xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;
- (xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;
- (xv) to co-operate with other National and International institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;
- (xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;
- (xvii) to enter into any agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Ordinance;
- (xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;
- (xix) to receive donations and grants and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;
- (xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;
- (xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission into the University;
- (xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;
- (xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of the Ordinance;
- (xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;
- (xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;

(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centers, off-shore campus, study centres as per the instructions issued by the State Government, Central Government and University Grants Commission from time to time; and

(xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund.—(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of three crore rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Ordinance, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Ordinance, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilised for the development of infrastructure of the University but shall not be utilised to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

- (a) fees and other charges received by the University;
- (b) any contribution made by the sponsoring body;
- (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;
- (d) bequests, donations, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:—

- (a) for the payment of salaries and allowances of the employees of the university and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;

- (b) for the expenses to be incurred by the university for services availed including services like electricity, telephone etc.;
- (c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;
- (d) for up keeping of the assets of the University;
- (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;
- (f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;
- (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Ordinance;
- (h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Ordinance;
- (i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (j) for the purpose of movable and immovable assets;
- (k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Ordinance or the statutes, Ordinances, regulations or rules made thereunder; and
- (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:—

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

(2) the Chancellor shall be the Head of the University.

(3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

- (a) to call for any information or record;
- (b) to appoint the Vice-Chancellor;
- (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Ordinance; and
- (d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for reappointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Ordinance, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Ordinance or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision

within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:—

- (i) the Governing Body;
- (ii) the Board of Management;
- (iii) the Academic Council; and
- (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;

- (c) five persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;
 - (d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;
 - (e) two persons, nominated by the Government; and
 - (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.
- (2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.
- (3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-
- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Ordinance or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
 - (b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this ordinance or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;
 - (d) to lay down the policies to be followed by the University;
 - (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and
 - (f) such other powers as may be prescribed by the statutes.
- (4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.
- (5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) two members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body;
 - (c) three persons, who are not the members of the Governing Body, nominated by the sponsoring body; and
 - (d) three persons from amongst the teachers, nominated by the sponsoring body.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.
- (3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.
- (4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Ordinance and the rules, statutes and ordinances made thereunder, coordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or
- (d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or
- (e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;
- (d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees and their powers and functions;
- (e) the terms and conditions of service of employees of the University;
- (f) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
- (i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
- (j) provisions regarding fees to be charged from the students; and
- (k) provisions regarding number of seats in different courses.

(2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) creation of new authorities of the University;
- (b) accounting policy and financial procedure;
- (c) representation of teachers in the authorities of the University;
- (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation of posts and procedure for abolition of posts;
- (g) revision of fees;
- (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and
- (i) all other matters which under the provisions of this Ordinance are to be specified by the statutes.

(2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Ordinance or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;
- (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and
- (k) all other matters which by this Ordinance or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions

made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Ordinance, the rules, statutes and the Ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per the policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval and the Government shall convey the approval within one month from the receipt of the proposal:

Provided that if the approval of the Government is not conveyed within one month, it shall be deemed to have been approved by the Government:

Provided further that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,-

- (a) sufficient for generating—
 - (i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and
 - (ii) the savings required for the further development of the University; and
- (b) not unreasonably excessive.

(3) After receipt of the recommendations under subsection (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.

(4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Government giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—‘Schedule of Examination means’ a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Government. The Government may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, within three years of its establishment and inform the Government and such other regulating bodies which are connected

with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation at an interval of every five years thereafter.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.—Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the University shall be bound to comply with all the rules, regulations, norms, etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under subsection (1) shall also be presented to the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Government.

(5) The advice of the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government may, after consultation with the Vice-Chancellor, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before fifteen years of its establishment all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Ordinance or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or maladministration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of contravening all or any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Ordinance or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under subsection (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
- (c) requisitioning any public record from any court or office; and
- (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Ordinance or the rules, statutes, or ordinances made there under or has violated any of the directions issued by it under this Ordinance or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and maladministration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Ordinance and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) matter to be prescribed under clause (d) of subsection (4) of section 42; and
- (b) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Ordinance.

(3) All the rules made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

PRABHA RAU,
Governor.
Himachal Pradesh.

Secretary (Law) to the
Government of Himachal Pradesh

Shimla
Dated:

उद्योग विभाग

संख्या: उद्योग-भू0(खनि-4)लघु-880 / 2005

शिमला -171001,.....

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला हमीरपुर की लघु खनिज खानों की नीलामी दिनांक 30-10-2009 को प्रातः 11.00 बजे खनि अधिकारी हमीरपुर जिला हमीरपुर के कार्यालय में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर से किसी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृत बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

- | | |
|--|--------|
| 1. जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है | 3 वर्ष |
| 2. जहां बोली पिछली बोली से 20 से 50 प्रतिशत अधिक प्राप्त होती है | 1 वर्ष |
| 3. जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो | 3 माह |

Auction Notice

It is for the information of general public that the minor mineral quarries of District Hamirpur are being put to public auction on 30-10-2009 at 11.00 A.M. in the office of the Mining Officer, Hamirpur, District Hamirpur, H.P. The interested persons may contact the Mining Officer, Hamirpur, for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department website www.himachal.nic.in/industry. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years on the basis of annual bid but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. policy given below:—

- | | |
|--|----------|
| 1. Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% | 3 years |
| 2. Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% | 1 year |
| 3. Where the bid exceeds the previous bid by less than 20% | 3 months |

जिला हमीरपुर में स्थित खड्डों/खानों का नीलामी प्रस्ताव

क्र० सं०	खड्ड का नाम	नीलामी का क्षेत्र	विवरण
1	जमीरी खड्ड	गांव दौल में वाटर सप्लाई स्कीम से 200 मीटर नीचे से महली पुल तक ।	महली पुल से उपर की ओर 300 मीटर तक खनन निषेध होगा व महली खड्ड (नाला) नीलामी का भाग नहीं होगा । दौल में खसरा नं०-1 तादादी क्षेत्र 12 कनाल 06 मरले नीलामी का भाग नहीं होगा ।
2	जगलेड खड्ड	जंगलबैरी में जगलेड खड्ड पर बने पुल से उपर की ओर वाटर सप्लाई स्कीम वोडू तक ।	---
3	पुंग खड्ड	री पुल से गांव टिककर डेबरा तक	---
4	ब्यास दरिया सुजानपुर	बलेहू से सचूही तक ।	टीका सचूही में खसरा नं० 6, 7, 8, 9 क्षेत्र 126 कनाल 03 मरले व खसरा नं० 25/1 क्षेत्र 14 कनाल 02 मरले नीलामी का भाग नहीं होगा ।
5	डेरा परोल खड्ड	गांव कजियाण से डेरा बाग तक ।	टीका रोपड़ी बलोहिया खसरा नं० 1 मिन क्षेत्र 13 कनाल 8 मरले नीलामी का भाग नहीं होगा ।
6.	कुनाह खड्ड-I	वाटर सप्लाई स्कीम मसियाणा से 300 मीटर नीचे से लेकर पटियाहू में परसराम के घराट तक ।	टीका बड़ेहड़ा में खसरा नं० 1361/1 क्षेत्र 1-92-00 है०, टीका जंगल में खसरा नं० 912, 1039, 1040, 751, 866, 1033, 1051 क्षेत्र 18-03-68 है० एवम् टीका वाड़ी में खसरा नं० 646 क्षेत्र 45 कनाल 11 मरले नीलामी का भाग नहीं होंगे ।
7.	वाकर खड्ड	गांव मतलाण से सधोल सड़क पर बने पुल तक ।	टीका पटनौण में खसरा नं० 1670, 995, 1003, 1238, 1576, 1577, 1578, 1579 क्षेत्र 538 कनाल 11 मरले, टीका करसोह खसरा नं० 2598, 2762, 2914 क्षेत्र 157 कनाल 15 मरले, टीका मतलाणा, मुआणा में खसरा नं० 1, 86, 506, 515, 516, 518, 539, 540, 547 व 1, 11, 462, 421, 429 क्षेत्र 354 कनाल 08 मरले, टीका खनोली में खसरा नं० 728 क्षेत्र 196 कनाल 15 मरले, एवम् टीका सचूही खसरा नं० 729 क्षेत्र 122 कनाल नीलामी का भाग नहीं होंगे ।
8	गारली खड्ड	गारली से सिरहाली बलियाह खड्ड के संगम तक ।	
9	सिरहाली बलियाह खड्ड	गांव थाना बलियां से बिलासपुर की ओर बहती खड्ड का जिला हमीरपुर में स्थित का पूर्ण भाग ।	खसरा नं० 142, 146, 1253, 1252 तथा टीका मलथ में वक्शी राम के घराट के चारों ओर 200 मीटर तक खनन प्रतिबन्धित होगा ।
10.	मसेह खड्ड	नादौन होशियारपुर रोड पर बने मसेह खड्ड पुल से उपर की ओर जिला हमीरपुर की खड्ड का पूर्ण भाग ।	टीका भवड़ा में खसरा नं० 554 क्षेत्र 2-33-87 हैक्टर नीलामी का भाग नहीं होगा ।

11.	मान खड्ड-II	करौर पुल से सुकड़िया पुल तक।	मौजा/टीका घड़ोह खसरा नं० 297/1 तादादी 5-37-60 है०, टंग खसरा नं० 886/1 तादादी 1-10-01 है०, डगोह डंडू खसरा नं० 234, 64, 317 तादादी 5-69-34 है०, जनसूह खसरा नं० 498 तादादी 7-60-65 है०, डडू खसरा नं० 415/36, 413/15, 416/36 तादादी 4-38-81 है० मौजा बलोह खसरा नं० 503/499/1, 503/499/2 तादादी 1-02-67 है० नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होंगे।
12.	मान खड्ड-III	सुकड़िया पुल से जौड़े अम्ब तक।	मौजा/टीका जसाई, घनोआ खसरा नं० 846 तादादी 2-51-67 है०, मनसाइ, खसरा नं० 1597 तादादी 1-65-61 है०, रासडा, कसवाड़ खसरा नं० 946, 947 तादादी 2-43-35 है०, सदोह, तूणी खसरा नं० 978/1, 1505/1 तादादी 2-60-26 है० मौजा कंगड़, धुनानी खसरा नं० 757/2 तादादी 35 कनाल नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होंगे।
13.	धवीरी समताना-II	दख्योड़ा से टीका चौकी तक	
14.	ब्यास दरिया नादौन	चौडू से चामुखा तक	टीका कलूर में खसरा नं० 1/1 क्षेत्र 0-96-36 हैक्टर नीलामी का भाग नहीं होगा।
15.	सीर खड्ड	चन्दरुही से जाहू में ब्रहमदास के घराट तक।	टीका जाहू में खसरा नं० 1739/870/1 क्षेत्र 28 कनाल, टीका बडैहर में खसरा नं० 2164/1862, 2169/1863, 2166/1862, 2168/1863 क्षेत्र 17 कनाल 10 मरले नीलामी का भाग नहीं होंगे।

नीलामी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी :

1. नीलामी के नियम व शर्तें हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित की जाएगी।
2. बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी।
3. कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास 5000/-रुपये धरोहर राशि अग्रिम रूप में जमा करवाएगा, जो बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दी जाएगी। नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा सकती है।
4. यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त भाग जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर धन राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।
5. जिन खानों को नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं० या फिर सीमा चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि खनि अधिकारी ने प्रस्तावित किये हैं जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
6. नदी/खड्डों की नीलामी प्राकृतिक व अन्य चिन्हों के आधार पर की गई है तथा नदी/खड्ड का वह क्षेत्र इन्हीं चिन्हों के मध्य ही नीलामी के लिए, जहां है जैसा है के आधार पर इस शर्त पर

प्रस्तावित किया गया है कि अगर प्रस्तावित चिन्हों के मध्य में कोई वन भूमि है तो प्रार्थी को वन विभाग का अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रस्तावित चिन्हों के मध्य किसी व्यक्ति की निजी भूमि आती हो तो उच्चतम बोलीदाता को उपरोक्त क्षेत्र में खनन करने के लिए प्रवेश करने से पूर्व निजी भूमि मालिक से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई निजी भूमि मालिक उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त किसी अन्य के पक्ष में अन्नापति प्रमाण पत्र देता है तो वह अन्नापति मान्य नहीं होगी, और निजी भूमि मालिक को उस क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे समस्त निलाम क्षेत्र के खनिज अधिकार उच्चतम बोली दाता के पक्ष में दिए गये हैं।

7. बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में सूचि में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकते हैं।
8. पीठासीन अधिकारी को अधिकार दिये गये हैं कि वह राजस्व एवम् जनहित में विभिन्न खानों का एक समूह या एक खान के छोटे-छोटे भाग बिना बताये कर सकता है। इसमें सभी इच्छुक बोलीदाता के सुझाव लिए जा सकते हैं।
9. बोलीदाता किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता जो विभाग के बकायादार होने में दोषी पाया जाये तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर दें तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकेगा। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान हो जाए तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि बकाया राशि में समायोजित की जाएगी और खान को पुनः नीलाम किया जाएगा।
10. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अवधि 3 वर्ष होगी तथा स्लेट खानों के मामले में अवधि 5 वर्ष होगी।
11. उत्खनी के बोली समाप्त होते ही वांछित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी:
 - (i) जहां पर बोली राशि 1000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा। विक्री कर भी उक्त राशि के अतिरिक्त उसी समय जमा करवाना पड़ेगा। प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 के रूप में ली जाएगी।
 - (ii) जहां बोली 1000/-रु0 से कम होगी वहां समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा कराने होंगे।
12. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
13. सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।
14. कोई भी खनन कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा तथा अन्य शर्तें सरकार द्वारा दिनांक 28-2-2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम बैंड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। अधिसूचना की प्रति खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के मध्य नीलामी कमेटी यदि कोई अन्य शर्त उद्घोषित करे वह भी मान्य होगी।

15. बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्यवहार करे तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
16. बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट न ले तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य न होगी।
17. नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज खानों का क्षेत्र अधिसूचना में दर्शाया गया ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त खानों के स्थित नक्शे/राजस्व रिकार्ड जो सम्बन्धित खनि अधिकारी/महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र के पास होंगे, उन पर दर्शाया गया क्षेत्र ही अधिसूचित लघु खनिज खानों का क्षेत्र मान्य होगा।
18. यदि नीलाम की गई लघु खनिज खानों का ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलाम की गई खान का कब्जा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।
19. बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनावार्ड नहीं की जाएगी।
20. सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज संशोधित नियमावली, 1971 के नियम-33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार उस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।
21. जहां-जहां भी स्पेन द्वारा खनिजों की ढुलाई करने की आवश्यकता हो उस अवस्था में स्पेन का अलाईनमेंट को ठेकेदार द्वारा विभाग से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा तथा स्पेन रंगीन रंग से चिह्नित करना होगा ताकि वह दूर से नज़र आये। जहां आवश्यकता हो, इसकी अनुमति वन विभाग से लेनी पड़ेगी। इसके लिए बने अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
22. खनन कार्य यदि वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित (खनन मापदण्डों के अनुरूप) ढंग से नहीं किया गया तो उस अवस्था में ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
23. पर्यावरण के हित में जहां सम्भव हो या विभाग द्वारा दर्शाया जाये वहां ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू-स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा जमानत राशि से यह काम कराया जाएगा तथा ठेकेदार को उतनी मात्रा की अलग से जमानत राशि जमा करानी होगी।
24. उक्त के अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्त पर्यावरण के संतुलन हेतु लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको मानने के लिए बाध्य होगा।
25. उच्चतम बोलीदाता सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए विक्री कर व अन्य कर देने के लिए बाध्य होगा।
26. नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी तथा नीलामी आरम्भ

होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी इसके अतिरिक्त खानों के बारे जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।

27. नीलाम-शुदा क्षेत्र में उच्चतम बोलीदाता खनन करते हुए इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगा कि उनके द्वारा किए गये खनन कार्य से भूमि कटाव न हो और नदी का वास्तविक बहाव न बदले। खड्डों/नालों के तटों को तोड़ना एक गम्भीर अपराध माना जाएगा तथा ऐसी अवस्था में ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा अमानत राशि सरकार में निहित कर ली जाएगी।
28. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
29. खनन हेतु मशीन उपकरण जैसे जे0सी0बी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है।
30. उपरोक्त चिन्हों के मध्य खनन कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्जित होगा :
 - वन या किसी अन्य विभाग द्वारा भू-संरक्षण के लिए लगाये गए चैक डैम इत्यादि, पौधारोपण, नर्सरी इत्यादि से 75 मीटर की दूरी तक।
 - नदी/खड्ड के तट से (दोनों तरफ) 5 मीटर या फिर नदी/खड्ड की चौड़ाई का पांचवां हिस्सा जो भी अधिक हो, तक।
 - पेयजल योजना या सिंचाई योजना के 200 मीटर ऊपर व 200 मीटर नीचे तक के स्थल पर।
 - पुल के 200 मीटर ऊपर व 200 मीटर नीचे तक।
31. नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से रास्ता बनाने हेतु उच्चतम बोलीदाता को अधिशाषी अभियन्ता (लो0नि0वि0) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
32. पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
33. उच्चतम बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
34. खनन कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट के गहरे गड्ढे करने की अनुमति नहीं होगी।
35. उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खनन कार्य का पुनः निरीक्षण (Review) किया जाएगा तथा अव्यवस्थित खनन करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
36. उप मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित क्षेत्र ही नीलाम किया जाएगा, जिसका विस्तृत रिकार्ड सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।
37. उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधि तय की जाएगी।

38. यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोनक्रशर स्थापना हेतु खनन पट्टा पर प्रदान करने के लिए नीलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में खड्ड का वह भाग अथवा क्षेत्र नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०

तारीख पेशी : 23-10-2009

गांव : सकरेड

श्री शशी पाल पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव सकरेड, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थी।

बनाम

1. शीला देवी विधवा श्री बाबू राम, 2. मुकेश पुत्र श्री बाबू राम नाबालग द्वारा माता शीला देवी,
3. जगदीश कुमार पुत्र श्री बाबू राम, 4. नीरो, 5. सुनीता, 6. कान्ता पुत्रियां श्री बाबू राम, निवासी गांव सकरेड,
तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश आम जनता . . फरीकदोयम।

आवेदन-पत्र अधीन धारा 40-41 भारतीय पंजीयन अधिनियम।

समन बनाम उपरोक्त फरीकदोयम।

उपरोक्त विषय पर आवेदन शशी पाल पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव सकरेड ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता स्व० श्री बाबू राम, निवासी सकरेड ने दिनांक 24-5-2009 को रोवरु गवाहन लेखक शेर सिंह पुत्र श्री बसन्त राम, निवासी मामणू से एक वसीयत नामा तहरीर करवाई है जोकि उनकी बिमारी के कारण कार्यालय उप-पंजीकाध्यक्ष सदर/नम्होल में पंजीकृत नहीं करवाई जा सकी है। अतः अब उसे पंजीकृत करने की अनुकम्पा करें।

अतः इशतहार से सभी सम्बन्धित फरीकदोयम को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को स्व० श्री बाबू राम द्वारा दिनांक 24-5-2009 को तहरीर करवाई गई वसीयतनामा को पंजीकृत करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/एतराज दिनांक 23-10-2009 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। गुजरने दिनांक 23-10-2009 के उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा वसीयतनामा को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-9-2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-पंजीकाध्यक्ष सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०

तारीख पेशी : 23-10-2009

गांव : मेन मार्किट

श्री जीत सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी मकान नं० 80-बी, मेन मार्किट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

आवेदन—पत्र अधीन धारा 40—41 भारतीय पंजीयन अधिनियम करने पंजीकृत वसीयत मृतक स्व0 श्री गोबिन्द राम पुत्र श्री सन्तु, निवासी मकान नं0 80—बी मेन मार्किट, बिलासपुर, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जीत सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी मकान नं0 80—बी, मेन मार्किट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन—पत्र गुजारा है कि स्व0 श्री गोबिन्द राम, निवासी मकान नं0 80—बी, मेन मार्किट बिलासपुर द्वारा तहरीर करवाई गई वसीयत को पंजीकृत करने की अनुकम्पा करें तथा आवेदन—पत्र में आम जनता को फरीकदोयम बनाया गया है।

अतः उक्त इशतहार के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त वसीयतनामा को पंजीकृत करने में किसी किस्म का कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23—10—2009 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वसीयतनामा स्व0 श्री गोबिन्द राम, निवासी 80—बी, मेन मार्किट, बिलासपुर, हि0 प्र0 को पंजीकृत कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 8—9—2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप—पंजीकाध्यक्ष सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री शशी पाल शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप—तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

श्री दीना नाथ पुत्र श्री हीरा लाल पुत्र श्री कक्खू, निवासी कामली, परगना अजमेरपुर, उप—तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम त्रुटि की शुद्धि हेतु।

श्रीयुत दीना नाथ पुत्र श्री हीरा लाल पुत्र श्री कक्खू, निवासी गांव कामली, परगना अजमेरपुर द्वारा अपने तथा अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख में त्रुटि के सुधार हेतु एक शपथ—पत्र एवं अन्य साक्ष्यों के साथ आवेदन किया है जिसके अनुसार उनका नाम गलती से दीना नाथ पुत्र श्री हीरा लाल की बजाए साई पुत्र घनसारा दर्ज हुआ है। जिसकी त्रुटि में सुधार हेतु निवेदन किया है।

अतः इस विज्ञापन के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में सुधार के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति अथवा उजर किसी संस्था को हो तो वह दिनांक 9—11—2009 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा सम्बद्ध प्रविष्टि में सुधार हेतु आवश्यक आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 17—9—2009 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

शशी पाल शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
उप—तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री धर्म दत्त व अन्य पुत्रगण श्री जुगू, निवासी खियूरी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

प्रार्थी श्री धर्म दत्त ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि भूमि खाता खतौनी नम्बर 92/201, खसरा नम्बर 242, रक्वा तादादी 0—9—1 बीघा मौजा खियूरी, तहसील सदर, जिला मण्डी के कागजात माल में खाना काश्त की जगह वाशिन्दग परदादा दूगना पुत्र मनीया का गलत इन्द्राज चढ़ा हुआ है क्योंकि खाना मालीक में बादीगणों का नाम ही बजौर मालिक दर्ज है तथा मौका पर भी वही उक्त भूमि के मालिक चले आ रहे हैं तथा उन्हीं का बादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जिस बारा प्रार्थीगणों ने उक्त इन्द्राज की दुरुस्ती बारा दरखास्त दी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व हितवद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है की यदि किसी को इस दुरुस्ती इन्द्राज बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में अपने एतराज दिनांक 23—10—2009 से पहले प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी उजर/एतराज काबले समायत न होगा तथा राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4—9—2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप—पंजीकाध्यक्ष तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्रीमती लज्जा देवी पत्नी श्री बली राम, निवासी मकान नं0, 86/5, पैलेस कलौनी मण्डी, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थीन।

बनाम

आम जनता

.. प्रत्यार्थी।

विषय.—पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 व 41 वसीयत का पंजीकरण बारे।

श्रीमती लज्जा देवी पत्नी श्री बली राम, निवासी मकान नं0, 86/5, पैलेस कलौनी तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है स्व0 बली राम पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी मकान नं0 86/5 पैलेस कलौनी, तहसील सदर, जिला मण्डी ने एक वसीयत करवाई है जोकि पंजीकृत ना है। बली राम की मृत्यु दिनांक 9—5—09 को हुई है मृत्यु प्रमाण—पत्र, प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है व वसीयत की प्रति भी प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को बली राम की वसीयत दिनांक 26—11—2007 के बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपने

एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 20-10-2009 को पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी उजर/एतराज काबले समायत न होगा तथा वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-9-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-पंजीकाध्यक्ष,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

1. श्री केसर सिंह, 2. तरुण कुमार पुत्रगण श्री लेख राम, 3. देवेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह नावालिग संरक्षक माता श्रीमती निर्मला देवी चलाह, डाकघर गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
.. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

.. प्रत्यार्थी।

विषय.—पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 व 41 वसीयत का पंजीकरण बारे।

श्री केसर सिंह आदि पुत्रगण श्री लेख राम, निवासी चलाह, डाकघर गुटकर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि बली राम पुत्र श्री नरंजन सिंह, निवासी चलाह, तहसील सदर, जिला मण्डी ने वसीयत करवाई है जोकि पंजीकृत ना है। बली राम की मृत्यु दिनांक 15-1-09 को हुई है मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है व वसीयत की प्रति भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की गई है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है की यदि किसी व्यक्ति/रिश्तेदार को बली राम की वसीयत दिनांक 1-1-2009 के बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपने एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 20-10-2009 को पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी उजर/एतराज काबले समायत न होगा तथा वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-9-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-पंजीकाध्यक्ष,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।